पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
विविध अपील संख्या 319/2020

बिमलेश कुमार पुत्र स्वर्गीय कपिलदेव राय, निवासी गांव-भावदेवपुर, थाना रीगा, जिला-सीतामढ़ी।

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. कपिलदेव नारायण राय पुत्र स्वर्गीय युगल किशोर यादव, निवासी गांव-कपिल राँय गली, न्यू जेरोमाइल, दक्षिण से कृषि बाजार समिति, थाना अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर ।
2. गंगा देवी, पत्नी कपिलदेव नारायण राय, निवासी गांव-कपिल राँय गली, न्यू जेरोमाइल, दक्षिण से कृषि बाजार समिति, थाना अहियापुर, जिला-मुजफ्फरपुर ।

..... उत्तरदातागण

शानवी, दामाद बिमलेश कुमार (अपीलार्थी) उपरोक्त पते पर उत्तरदाताओं के साथ रहने वाले प्रतिवादी/

उपस्थिति :

अपीलकर्ता/ओं के लिए : सुश्री निवेदिता निर्विकर, वरिष्ठ अधिवक्ता।
सुश्री शशि प्रिया, अधिवक्ता।
उत्तरदाताओं के लिए : श्री राजेन्द्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री जितेंद्र कुमार राँय, अधिवक्ता।

अधिनियम/धाराएं/नियम: • फैमिली कोर्ट अधिनियम, 1984 की धारा 19(1)

• संरक्षक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 19, 25

• हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 4(ग)

उल्लेखित प्रकरण: • निल रतन कुंडू बनाम अभिजीत कुंडू (2008) 9 एससीसी 413 में रिपोर्ट किया गया

मौसमी मोइत्रा गांगुली बनाम जयंत गांगुली की रिपोर्ट (2008) 7 एससीसी 673

अतहर हुसैन बनाम सैयद सिराज अहमद और अन्य, एआईआर 2010 एससी 1417 में रिपोर्ट किया गया

अंजलि कपूर (श्रीमती) बनाम राजीव बैजल (2009) 7 एससीसी 322 में रिपोर्ट की गई

सोमप्रभा राणा एवं अन्य। बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य। (2024) 9 एस.सी.आर. में रिपोर्ट किया गया। 64

अपील - परिवार न्यायालय द्वारा संरक्षकता मामले में पारित उस निर्णय के विरुद्ध दायर की गई, जिसमें नाबालिग बालिका की अभिरक्षा को उत्तरवादियों से अपीलकर्ता-पिता को हस्तांतरित करने हेतु दायर आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया।

निर्णय - यह विधिसिद्ध है कि नाबालिग बालक/बालिका की अभिरक्षा हेतु आवेदन, न्यायालय की पालक प्रतिनिधि क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होता है और न्यायालय द्वारा निर्णय लेते समय मुख्य विचार नाबालिग की सर्वोपरि कल्याण होता है। (पैरा 18)

नाबालिग बालिका लंबे समय से ननिहाल (मातृ पक्ष) के संरक्षण में है और वह अपने पिता की अभिरक्षा में सहज प्रतीत नहीं होती। इस अवस्था में अभिरक्षा हस्तांतरित करने से बालिका को अधिक मानसिक आघात होगा। (पैरा 26)

वर्तमान स्थिति में नाबालिग बालिका के कल्याण हेतु अभिरक्षा में कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं है। यदि बालिका की अभिरक्षा तुरंत पिता को दे दी जाती है, तो वह मानसिक रूप से दुखी हो सकती है, क्योंकि वह अपने पिता के प्रति निकटता अनुभव नहीं करती। मनोवैज्ञानिक परामर्श रिपोर्ट एवं पक्षकारों व नाबालिग बालिका के साथ हुई बातचीत से यह स्पष्ट है कि उत्तरवादी उसकी उचित देखभाल कर रहे हैं, उसे सम्मानजनक जीवनशैली, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं समग्र बौद्धिक विकास प्रदान कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपीलकर्ता नाबालिग की प्राकृतिक अभिभावक हैं, परंतु वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि बालिका अपने ननिहाल में ही रहे, जब तक वह बालिग न हो जाए या बाद में स्वयं पिता के साथ रहने का निर्णय न ले। प्राकृतिक पिता होने के नाते, अपीलकर्ता को अपनी पुत्री से मिलने का अधिकार है और यह बालिका के समग्र विकास के हित में है कि वह अपने पिता से नियमित और सार्थक संपर्क में रहे। (पैरा 27)

अपील खारिज की जाती है। (पैरा 29)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

न्यायालय: माननीय न्यायमूर्ती श्री पी. बी. भजंत्री और

माननीय न्यायमूर्ती श्री सुनील दत्ता मिश्रा

सी. ए. वी. जजमेंट

(प्रति: माननीय न्यायमूर्ती श्री सुनील दत्ता मिश्रा)

तारीख:07-04-2025

पक्षकारों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. वर्तमान विविध अपील परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के तहत विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सीतामढ़ी द्वारा संरक्षकता वाद संख्या 02/2018 में पारित दिनांक 27.02.2020 के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत और जहां संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 25 के तहत प्रतिवादियों से अपीलकर्ता को नाबालिग बालिका की अभिरक्षा हस्तांतरित करने के आवेदन को कुछ निर्देशों के साथ खारिज कर दिया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलार्थी विमलेश कुमार और स्वर्गीय प्रभा कुमारी (प्रत्यर्थियों की बेटी) की शादी 17.01.2013 को हुई थी। शानवी यादव नामक एक लड़की का जन्म उनकी शादी से 17.02.2015 को हुआ था। अपीलार्थी भारतीय स्टेट बैंक में बैंक प्रबंधक हैं। वर्ष 2015-16 में उन्हें दिल्ली में तैनात किया गया था जहाँ मृतक (प्रभा कुमारी) ने जनवरी 2016 में गर्भधारण (दूसरी गर्भावस्था) की थी। अपने दूसरे बच्चे की उचित देखभाल और प्रसव के लिए वह नाबालिग बेटी के साथ जुलाई, 2016 के महीने में मुजफ्फरपुर में अपने माता-पिता के घर गई, जहाँ वह बाथरूम में एक दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसके परिणामस्वरूप 08.08.2016 को उसकी मौत हो गई। नाबालिग बेटी अपनी बेहतर देखभाल के लिए अपने नाना-नानी (उत्तरदाताओं) के साथ रही। इस पृष्ठभूमि में कहा जाता है कि अपीलार्थी को सितंबर, 2016 के महीने में नई दिल्ली से पटना स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद, उन्होंने दूसरी बार पूजा कुमारी से 18.04.2017 को शादी की। दूसरी शादी से, उन्हें एक बेटा हुआ, जिसका नाम प्रियेश यादव है। अपीलार्थी की पहली शादी की बेटी मुजफ्फरपुर में अपने नाना-नानी (उत्तरदाताओं) के साथ रह रही थी और जब

अपीलार्थी अपनी नाबालिग बेटी से मिलने गया, तो उसे उससे मिलने और बात करने की अनुमति नहीं दी गई। जब अपीलकर्ता अनेक प्रयासों के बाद भी अपनी नाबालिग बेटी से मिलने और बात करने में सफल नहीं हुआ तो अपीलकर्ता ने बालिका शानवी यादव की अभिरक्षा के लिए संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 25 के तहत याचिका दायर की।

4. अपीलार्थी का मामला यह है कि उत्तरदाता वृद्ध व्यक्ति हैं जो नाबालिग बच्चे की देखभाल करने और उसे अच्छी जीवन शैली प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं और वे स्वयं शारीरिक और आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर हैं। तदनुसार, यह नाबालिग बच्चे के कल्याण में है कि अपीलार्थी उसकी अभिरक्षा प्रदान करे जो नाबालिग लड़की के स्वाभाविक संरक्षक होने के नाते बेहतर तरीके से देखभाल करने में सक्षम है।

5. प्रत्यर्थियों का मामला यह है कि प्रत्यर्थियों की बेटी स्वर्गीय प्रभा कुमारी अपीलार्थी के साथ खुशहाल जीवन नहीं जी रही थी और लड़की का जन्म प्रतिवादी की उपस्थिति में मुजफ्फरपुर के बथुआ नर्सिंग होम में हुआ था और वह अपनी गर्भावस्था के दौरान गंभीर थी और चिकित्सा सलाह के खिलाफ, उसे अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थियों के घर ले जाया गया था, इसके बाद, अपीलार्थी दिल्ली लौट आया जो मृत प्रभा देवी और उसकी बेटी के प्रति उसके लापरवाही भरे व्यवहार को दर्शाता है। अपीलार्थी ने नाबालिग बेटी को प्रत्यर्थियों के पास छोड़ दिया और अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के एक वर्ष के भीतर अपनी दूसरी शादी कर ली। प्रत्यर्थी संख्या 1 एक सेवानिवृत्त इंजीनियर है और उसे एक मानक जीवन शैली जीने के लिए पर्याप्त पेंशन मिलती है और वे नाबालिग बच्चे की देखभाल करने और उसे एक अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करने में सक्षम हैं।

6. दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर, विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा 21.11.2019 पर निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे:

(i) क्या आवेदक द्वारा दायर किया गया मुकदमा विचारणीय है या नहीं?

(ii) क्या आवेदक को नाबालिग लड़की के कानूनी अभिभावक के रूप में इस मुकदमे को लाने का अधिकार और कारण है? या, क्या शानवी के नाना-नानी होने का दावा

करने वाले प्रतिद्वंद्वी का दावा शानवी की मां प्रभा कुमारी की मृत्यु से पहले और बाद की परिस्थितियों के आलोक में आवेदक को शानवी की अभिरक्षा दिलाने के लिए उचित है?

(iii) क्या इस मामले में निर्णय लेने से पहले नाबालिग की इच्छाओं और उसके कल्याण पर विचार करना उचित है?

(iv) क्या आवेदक अभिभावक और प्राकृतिक अभिभावक होने के अपने दावे के आलोक में नाबालिग बालिका के संरक्षकता और न्यासी होने का हकदार है या नाबालिग बालिका को विरोधी पक्ष की अभिरक्षा में दिया जाना चाहिए?

(v) आवेदक या विरोधी पक्ष के पक्ष में और क्या राहत या राहत दी जानी चाहिए?

7. याचिकाकर्ता/अपीलार्थी की ओर से तीन गवाहों से पूछताछ की गई है। अभियोजन साक्षी-1 पूजा कुमारी है जो अपीलार्थी की दूसरी पत्नी है; अ0सा0-2 राजेश कुमार जो अपीलार्थी का भाई है और अ0सा0-3 खुद याचिकाकर्ता बिमलेश कुमार है। दूसरी ओर, प्रत्यर्थियों की ओर से तीन गवाहों से पूछताछ की गई है। विपक्षी साक्षी -1 नाबालिग शानवी @शानवी यादव है; वि0सा0-2 गंगा देवी प्रतिवादी संख्या है। 2 और वि0सा0-3 कपिलदेव नारायण रे प्रतिवादी नं.1 है।

8. विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सीतामढी ने अभिलेख पर साक्ष्य और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद अपीलार्थी के खिलाफ और उत्तरदाताओं के पक्ष में मुद्दों का फैसला किया और कहा कि स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थी नाबालिग बच्चे का स्वाभाविक अभिभावक है, लेकिन वर्तमान स्थिति में नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा तब तक उत्तरदाताओं के साथ बनी रहेगी जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाती या प्रतिवादी जीवित हैं या नाबालिग खुद अपने माता-पिता के साथ नहीं जाना चाहती है। अपीलार्थी को उसकी दूसरी पत्नी और उसके बेटे के साथ अपनी बेटी से मिलने का अधिकार दिया गया है और प्रतिवादी इसका विरोध नहीं करेंगे। विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि जब भी प्रतिवादीगण नाबालिग शानवी के भरण-पोषण में कठिनाई महसूस करें, तो वे नाबालिग लड़की शानवी की अभिरक्षा अपीलकर्ता को सौंप दें तथा न्यायालय को सूचित करें, ताकि वह स्वयं को एक स्वस्थ,

शिक्षित एवं सक्षम नागरिक बना सके। नाबालिग बेटी की उच्च शिक्षा/विवाह व्यय/रोजगार के उद्देश्य से अपीलकर्ता को निर्देश दिया गया है कि वह शानवी के खाते में 13 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि सावधि जमा के रूप में जमा कराए, जो वयस्क होने पर उक्त राशि निकालने की हकदार होगी। जब तक वह व्यस्कता प्राप्त नहीं कर लेती।उत्तरदाता, यदि वे उक्त मासिक राशि नहीं निकालना चाहते हैं, तो वे नाबालिग शानवी के रखरखाव और शैक्षिक खर्चों के लिए खुद से खर्च कर सकते हैं।अनुपालन न होने की स्थिति में, नाबालिग बेटी के लिए उक्त राशि पर प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगी।यह स्पष्ट किया गया है कि नाबालिग होने के नाते अपीलार्थी की बेटी कानून के अनुसार अपीलार्थी की चल और अचल संपत्ति में बेटी के रूप में अपने हिस्से की हकदार होगी। उक्त आदेश के आलोक में, नाबालिग शानवी के रखरखाव के लिए अलग रखरखाव मामला संख्या 209/2019 का निपटारा कर दिया गया।

9. अपीलार्थी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान निचली अदालत ने मामले के तथ्यों का ठीक से आकलन किए बिना और बच्चे के कल्याण को ध्यान में रखे बिना दिनांक 27.02.2020 का आक्षेपित निर्णय पारित करते समय गलती की है, और यह अपास्त कियो जाने योग्य है।यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलकर्ता हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम, 1956 की धारा 4 (सी) के अनुसार नाबालिग लड़की का स्वाभाविक अभिभावक है और उसे अपनी नाबालिग लड़की की अभिरक्षा लेने का कानूनी अधिकार है।

10. अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि अभिभावक और वार्ड अधिनियम, 1890 की धारा 19 (बी) में कहा गया है कि न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति को नाबालिग के अभिभावक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत नहीं होगा, जिसका पिता जीवित है और अदालत की राय में नहीं है, जो नाबालिग के व्यक्ति का अभिभावक होने के लिए अयोग्य है। इसलिए, नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा नाबालिग के पिता के अलावा किसी और को सौंपते समय भी इसी तरह का विचार किया जाएगा।

11. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी पेशेवर रूप से अच्छी तरह से बसा हुआ है, अच्छी तरह से योग्य है और उसके पास अच्छी आय और अन्य संपत्तियां भी हैं जो नाबालिग

बच्चे को प्यार और माता-पिता का स्नेह और परिवार की देखभाल देने के लिए तैयार हैं, जिसे उसके सर्वांगीण विकास की आवश्यकता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे कहा कि अपीलार्थी का पुनर्विवाह बच्चे की अभिरक्षा नहीं देने का आधार नहीं है और बच्चे के कल्याण पर सर्वोपरि विचार किया जाना चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थियों का दुर्भावनापूर्ण इरादा इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी के खिलाफ देर से शिकायत का मामला दर्ज किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के लिए जिम्मेदार है जो नाबालिग बच्चे के निर्दोष मन में उसके प्रति नकारात्मक प्रभाव डालेगा। अपीलकर्ता अपने नाबालिग बच्चे शानवी को उचित और बेहतर देखभाल, शिक्षा और जीवन की गुणवत्ता दे सकता है।

12. उन्होंने आगे कहा कि उत्तरदाता अपनी वृद्धावस्था के कारण बालिकाओं की उचित देखभाल नहीं कर सकते हैं और उन्हें जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान नहीं कर सकते हैं। यह कहा गया है कि अपीलार्थी अपनी मृत पत्नी (नाबालिग बेटी की माँ) के साथ एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहा था। बालिका अपीलार्थी, उसकी सौतेली माँ और छोटे सौतेले भाई के साथ समय बिताना चाहती थी, लेकिन उत्तरदाताओं ने उसे अपने पिता से मिलने और उनके साथ मिलने की अनुमति नहीं दी। प्रत्यर्थी की वास्तविक चिंता बालिका के कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि केवल उनके बड़े हुए अहंकार को संतुष्ट करने के लिए है।

13. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थियों से नाबालिग लड़की की अभिरक्षा को सही ढंग से बाधित नहीं किया है। यह आगे कहा गया है कि हालाँकि अपीलार्थी बालिका का स्वाभाविक संरक्षक है, लेकिन बच्चे का कल्याण सर्वोपरि विचार होना चाहिए। बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है और उत्तरदाताओं के संरक्षण में ठीक से पाला जा रहा है। इसके अलावा, यह कहा जाता है कि नाबालिग लड़की को सौतेली माँ के साथ अपने पिता की तुलना में उत्तरदाताओं से अधिक प्यार और स्नेह मिलेगा, जो बच्चे के उचित विकास के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, नाबालिग लड़की खुद अपीलार्थी और उसकी दूसरी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहती है। विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के साथ-साथ उसकी दूसरी पत्नी और उसके बेटे से मिलने का अधिकार दिया है और प्रतिवादियों को निर्देश दिया

है कि यदि वे उचित पोषण और जीवन की अच्छी गुणवत्ता प्रदान करने में सहज नहीं हैं, तो वे नाबालिग बच्चे शानवी की कस्टडी अपीलकर्ता को सौंप देंगे। विद्वत विचारण न्यायालय ने नाबालिग बच्चे के कल्याण का भी ध्यान रखा और नाबालिग बच्चे के उच्च शिक्षा और विवाह के खर्च के लिए उसके बैंक खाते में 10,00,000 रुपये जमा करने का निर्देश दिया और उसके भरण पोषण और शैक्षिक शुल्क के लिए 7,000 रुपये की मासिक राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया, जिसे अनुचित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अपीलकर्ता जो बैंक अधिकारी है उक्त आदेश का पालन करने के बजाय, उन उत्तरदाताओं के खिलाफ झूठा आरोप लगाया जो न केवल प्यार और स्नेह प्रदान कर रहे हैं, बल्कि उसे गुणवत्तापूर्ण जीवन और उचित शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि नाबालिग बच्चे के प्रति अपीलार्थी का आचरण दर्शाता है कि उसे बच्चे के कल्याण और हित में कोई दिलचस्पी नहीं है और यह अपील खारिज करने के योग्य है। इसलिए, बालिका के सर्वोपरि हित और कल्याण में, विद्वान परिवार न्यायालय के आदेश में इस अपील में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

14. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय को केवल एक ही सवाल का फैसला करना है

“ क्या विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27.2.2020 के निर्णय/आदेश में नाबालिग बच्चे के समग्र कल्याण और सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए इस अपील में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता है? ”

15. उत्तरदाता दुर्भाग्यपूर्ण माता-पिता हैं जिनकी बेटी की असामयिक मृत्यु हो गई थी और उन्हें उसकी माँ की मृत्यु के तुरंत बाद लड़की की अभिरक्षा सौंपी गई थी क्योंकि अपीलार्थी दिल्ली में बैंक में काम कर रहा था जो उस समय बच्चे की देखभाल करने में असमर्थ था और उत्तरदाता बच्चे की आवश्यकताओं का ध्यान रखने की स्थिति में थे। वे नाबालिग बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, जो केवल डेढ़ साल का था जब उसकी माँ का निधन हो गया था। विवाहित बेटी के गहरे नुकसान को देखते हुए, वे बच्चे के साथ गहरा भावनात्मक बंधन विकसित करने के लिए बाध्य हैं, जो उनकी एकमात्र जीवित स्मृति बनी हुई है।

16. अपीलार्थी की नाबालिग बेटी अब लगभग 10 वर्ष की हो गई है जो अपनी माँ की मृत्यु से पहले जुलाई, 2016 के महीने से अपने नाना-नानी/उत्तरदाताओं के साथ रह रही है। अपीलार्थी ने पूजा कुमारी (अ०सा०-1) के साथ अपनी दूसरी शादी कर ली है और उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद मिला है। अपीलार्थी एक अच्छी आय अर्जित करता है और एक वरिष्ठ बैंक प्रबंधक है। प्रत्यर्थी नं.1 एक सेवानिवृत्त इंजीनियर हैं। नाबालिग बच्ची ने अपने पिता-अपीलार्थी के साथ रहने की अनिच्छा व्यक्त की और वह उत्तरदाताओं के साथ सहज है जहां उसने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और अच्छी प्रगति की। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि वे स्वस्थ वातावरण प्रदान करके बच्चे का कल्याण चाहते हैं। दोनों पक्षों ने तर्क दिया कि बच्चे का कल्याण उनके लिए सर्वोपरि है।

17. नाबालिग बच्चे की कस्टडी के मामले में पिता के पक्ष में वैधानिक प्रावधान केवल उन परिस्थितियों में से एक है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन न्यायालय की मुख्य चिंता बच्चे का कल्याण होना चाहिए। कल्याण, जैसा कि विभिन्न निर्णयों में स्पष्ट किया गया है, में न केवल शारीरिक कल्याण बल्कि सदाचार पूर्ण और नैतिक कल्याण भी शामिल है।

18. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा के लिए आवेदन उसके पैरेंट्स पैट्रिया क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है और निर्णय लेते समय न्यायालय का मुख्य विचार नाबालिग बच्चे का सर्वोपरि 'कल्याण' होगा। इस संदर्भ में, नील रतन कुंडू बनाम अभिजीत कुंडू (2008) 9 एससीसी 413 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना उचित होगा, जिसमें नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा से जुड़े प्रश्नों पर निर्णय लेते समय न्यायालयों द्वारा विचार किए जाने वाले 'कल्याण' के मापदंडों और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया था। प्रासंगिक पैराग्राफ को इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“52. हमारे निर्णय में, बच्चे की अभिरक्षा से संबंधित कानून काफी हद तक स्थापित है और यह इस प्रकार है: नाबालिग की अभिरक्षा के रूप में एक कठिन और जटिल प्रश्न का निर्णय करते समय, न्यायालय को संबंधित विधियों और उनसे प्राप्त अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ऐसे मामलों का निर्णय केवल

कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करके नहीं किया जा सकता। यह एक मानवीय समस्या है और इसे मानवीय स्पर्श के साथ हल किया जाना चाहिए। अभिरक्षा मामलों से निपटते समय न्यायालय न तो विधियों से बंधा होता है, न ही साक्ष्य या प्रक्रिया के सख्त नियमों से और न ही मिसालों से। नाबालिग के लिए उचित अभिभावक का चयन करते समय, सर्वोपरि विचार बच्चे के कल्याण और भलाई का होना चाहिए। अभिभावक का चयन करते समय, न्यायालय पैरेंस पैट्रिया अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है और उससे अपेक्षा की जाती है कि वह बच्चे के सामान्य आराम, संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को उचित महत्व दे। लेकिन इसके अलावा, न्यायालय को बच्चे के सामान्य आराम, संतुष्टि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बौद्धिक विकास और अनुकूल परिवेश को उचित महत्व देने के लिए बाध्य होना चाहिए। भौतिक सुख-सुविधाओं से ऊपर नैतिक और नैतिक मूल्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वे समान रूप से, या हम कह सकते हैं, और भी अधिक महत्वपूर्ण, आवश्यक और अपरिहार्य विचार हैं। यदि नाबालिग बुद्धिमान वरीयता या निर्णय लेने के लिए पर्याप्त उम्र का है, तो अदालत को ऐसी वरीयता पर भी विचार करना चाहिए, हालांकि अंतिम निर्णय अदालत के पास होना चाहिए कि नाबालिग के कल्याण के लिए क्या अनुकूल है।

(जोर दिया गया)

19. इसके अलावा, याचिकाकर्ता का आरोप है कि प्रतिवादी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 एक सेवानिवृत्त इंजीनियर है और उनके साक्ष्य में यह कहा गया है कि उनके पास पर्याप्त संपत्ति और सुविधाएं हैं, और उनके बेटे और बहू विदेश में काम कर रहे हैं, जिसे अपीलकर्ता ने अस्वीकार नहीं किया है। हम इन परिस्थितियों में यह नहीं कह सकते कि नाबालिग बच्चे के हितों को किसी भी स्थिति में वित्तीय तंगी के कारण प्रतिवादियों की अभिरक्षा में रखने से नुकसान होगा।

20. **मौसमी मोइत्रा गांगुली बनाम जयंत गांगुली ने (2008) 7 एससीसी 673** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट दी कि पक्षों की वित्तीय स्थिति या वैधानिक अनुमान एकमात्र निर्णायक कारक नहीं हो सकता है और न्यायालय पर यह भारी कर्तव्य है कि वह प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में बच्चे के कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए अपने न्यायिक विवेक का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करे।

21. बच्चे की माँ की मृत्यु के बाद, प्रतिवादी स्वेच्छा से बच्चे की देखभाल करने का बीड़ा उठाते हैं। बच्चे का पालन-पोषण करना न केवल एक खुशी है, बल्कि इसमें एक जिम्मेदार कर्तव्य का निर्वहन भी शामिल है। बच्चे के नाना-नानी इतने सालों से बच्चे का पालन-पोषण बड़े प्यार और स्नेह से करते दिख रहे हैं और नाबालिग बच्चा पसंद करने के लिए बुद्धिमान पाया गया है। परिस्थितियों की समग्रता में, ऐसा कोई बाध्यकारी कारण नहीं है जो भावनात्मक लगाव और सुरक्षा के इस बंधन को तोड़ने को उचित ठहराए जो पिता ने खुद पाया है और बच्चे के बीच बढ़ने दिया है। और उसके दादा-दादी। हालांकि, नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा का दावा करने का पिता का अधिकार असीमित नहीं है और यह नाबालिग बच्चे के कल्याण के अधीन है। इसलिए, इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, इस चरण में बच्चे को अपीलकर्ता को सौंपने का निर्देश देना न्यायसंगत नहीं होगा।

22. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि संरक्षकता और अभिरक्षा दो अलग-अलग कारक हैं। **अतहर हुसैन बनाम सैयद सिराज अहमद और अन्य, एआईआर 2010 एससी 1417** में रिपोर्ट की गई अपीलकर्ता-पिता ने दूसरी बार शादी की थी और बच्चे अपनी मौसी और चाचा की अभिरक्षा में थे। यह माना गया कि हालांकि पिता की दूसरी शादी एक अयोग्य कारक नहीं थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण कारक था। न्यायालय ने बताया कि संरक्षकता और अभिरक्षा दो अलग-अलग कारक हैं। पिता को अभिभावक होने के योग्य पाया गया और उसे इस रूप में जारी रखने की अनुमति दी गई, लेकिन उसे अभिरक्षा से वंचित कर दिया गया।

23. यह विवाद में नहीं है कि पिता की भूमिका नाबालिग बच्चे के पालन-पोषण के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। पिता की देखभाल और मार्गदर्शन तथा नाबालिग बच्चे के पालन-

पोषण और जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने के लिए उसकी भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। इस मामले में नाबालिग बच्चे ने अपनी माँ को खो दिया है। पक्षों के बीच आरोप-प्रत्यारोप बच्चे में नकारात्मक भावनाएँ पैदा कर रहा है और पिता के प्रति नापसंदगी पैदा कर रहा है। यह नाबालिग और दोनों पक्षकारों के हित में होगा यदि वे अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लें, ताकि नाबालिग को अपने नाना-नानी के परिपक्व मार्गदर्शन और मजबूत समर्थन के साथ-साथ अपने पिता के प्यार और स्नेह से वंचित न होना पड़े।

24. इसी तरह के एक मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **अंजलि कपूर (श्रीमती) बनाम राजीव बैजल** के मामले में (2009) 7 एससीसी 322 में रिपोर्ट की, जहां पिता और नानी के बीच विवाद था, दादी को अभिरक्षा में दे दिया। बच्चा एक शिशु था जब बच्चे को जन्म देने के समय उसकी माँ की मृत्यु हो गई। दादी नाबालिग बच्चे की देखभाल करती रही। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि वह अपनी इकलौती बेटी के प्रति काफी देखभाल, स्नेह और प्यार रखती थी, जिसकी दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। न्यायालय ने नानी और आर्थिक रूप से संपन्न नानी के बीच मजबूत भावनात्मक बंधन पर विचार किया। पिता ने दूसरी शादी की थी और इस विवाह से उसे एक बच्चा भी था। इसलिए, नाबालिग बच्चे को सौतेली माँ की देखभाल में भेजने का विकल्प अनुकूल नहीं लगा और न्यायालय ने बच्चे की कस्टडी नानी के पक्ष में दे दी। उपरोक्त निर्णय के पैरा 23 में यह देखा गया है कि बच्चा काफी समय तक दादी के पास रहा था और अपने विकास के लिए अनुकूल वातावरण में बड़ा हो रहा था, इसलिए इस स्तर पर उस वातावरण को बदलना उचित नहीं हो सकता है जिसका बच्चा आदी हो गया है।

25. वर्तमान में, नाना-नानी जीवित हैं और अपनी बेटी की मृत्यु के बाद इस नाबालिग बच्चे से प्यार करते हैं। यह तर्क कि एक न एक दिन नाबालिग को अपीलकर्ता-पिता के साथ रहना ही है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। आज हम बच्चे के जीवन में आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। वर्तमान परिस्थितियों में अनिश्चित भविष्य के आधार पर बच्चे को पिता को सौंपने का निर्देश देना उचित नहीं है। हमारे विचार से, बच्चे को जिस सुरक्षा की आवश्यकता है, जो गर्मजोशी और स्नेह उसे आज मिल सकता है, वह निस्संदेह

अपीलकर्ता-पिता की तुलना में नाना-नानी के साथ अधिक होगा। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह नहीं माना जाता है कि अपीलकर्ता अपनी नाबालिग बेटी शानवी का कानूनी अभिभावक होने के लिए अयोग्य है। परिस्थितियों की गतिशील प्रकृति और समय बीतने पर विचार करते हुए, न्यायालय बच्चे के सर्वोत्तम हित में ऐसे आदेशों को आवश्यकतानुसार बदलने का अधिकार रखता है। यदि स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, जिसके लिए पुनर्विचार की आवश्यकता होती है, तो पक्षकार न्यायालय से उचित निर्देश/आदेश प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।

26. यह स्पष्ट है कि नाबालिग बच्चा काफी समय तक नाना-नानी की अभिरक्षा में रहा है और पिता की अभिरक्षा में सहज नहीं लग रहा था और इस स्तर पर अभिरक्षा सौंपने से बच्चे को और अधिक आघात पहुंचेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **सोमप्रभा राणा एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य** के मामले में (2024) 9 एस.सी.आर. 64 में रिपोर्ट की, कि न्यायालय बच्चे को चल संपत्ति के रूप में नहीं मान सकता है और अभिरक्षा में गड़बड़ी के बच्चे पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किए बिना अभिरक्षा हस्तांतरित नहीं कर सकता है। ऐसे मुद्दों को यंत्रवत् तय नहीं किया जा सकता है और न्यायालय को मानवीय विचारों के आधार पर कार्य करना होगा।

27. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर, नाबालिग बच्चे के कल्याण के लिए प्रतिवादियों से अभिरक्षा में बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यदि बच्चे की अभिरक्षा तुरंत अपीलकर्ता-पिता को हस्तांतरित कर दी जाती है, तो बच्चा दुखी हो जाएगा क्योंकि उसके पास अपने पिता के प्रति आत्मीयता की कमी है। इसके अलावा, मनोवैज्ञानिक परामर्श रिपोर्ट और पक्षों और नाबालिग बच्चे के साथ बातचीत सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों से, यह पाया गया है कि प्रतिवादी नाबालिग लड़की की उचित देखभाल कर रहे हैं और उसे सभ्य जीवन शैली, अच्छी शिक्षा और समग्र बौद्धिक विकास प्रदान कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता नाबालिग बेटी का प्राकृतिक अभिभावक है, हालांकि, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार नाबालिग लड़की को उसके नाना-नानी की अभिरक्षा में रहना होगा, जब तक कि वह वयस्क नहीं हो जाती या उसके बाद अपने पिता के साथ रहने का विकल्प नहीं चुन

लेती। प्राकृतिक पिता होने के नाते, अपीलकर्ता को बच्चे से मिलने का अधिकार है और यह बच्चे के सर्वोत्तम हित में है कि वह अपने पिता के साथ सार्थक और नियमित बातचीत बनाए रखे ताकि उसका समग्र विकास हो सके।

28. विवादित निर्णय और आदेश के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधान न्यायाधीश ने नाबालिग बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए सभी स्थितियों और भविष्य की संभावनाओं का ध्यान रखा है। नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा और भरण-पोषण के संबंध में विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा की गई व्यवस्था को अनुचित नहीं माना जा सकता।

29. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, अभिभावकत्व मामले संख्या 02/2018 में विद्वान पारिवारिक न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 27.02.2020 के निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, तदनुसार, वर्तमान विविध अपील खारिज की जाती है।

30. अंतरिम आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

31. अपीलकर्ता को उक्त निर्णय में उल्लिखित विभिन्न निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें उक्त राशि पर दिनांक 27.02.2020 के आक्षेपित निर्णय की तिथि से भुगतान की तिथि तक 6% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि जमा करना और इस निर्णय की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर रखरखाव राशि का बकाया भी जमा करना शामिल है और अपीलकर्ता द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति में, विद्वान ट्रायल कोर्ट को उसके वेतन से कटौती और/या उसकी संपत्ति की कुर्की के निर्देश सहित सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है।

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

में भी सहमत हूँ

पी. बी. भजंगी, न्यायमूर्ति

(पी. बी.भजंगी, न्यायमूर्ति)

ऋतिक/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।